



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मंगलवार को विधानसभा में संसदीय राजभाषा समिति गृह मंत्रालय की प्रथम उप समिति के संयोजक और सांसद डॉ. दिनेश शर्मा एवं समिति के सदस्यों ने मुलाकात की। डॉ. दिनेश शर्मा उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं और 2017 से 2022 तक उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री रहे हैं। डॉ. दिनेश शर्मा के नेतृत्व वाली उपसमिति विभिन्न सरकारी कार्यालयों में हिन्दी कार्य संचालन का निरीक्षण करती है।

## आतिशी सहित आप के 21 विधायक तीन दिन के लिए निलंबित

नयी दिल्ली, 25 फरवरी। दिल्ली विधानसभा में उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण के दौरान हंगामे और नारेबाजी के कारण नेता विपक्ष आतिशी समेत आम आदमी पार्टी (आप) के 21 विधायकों को तीन दिन के लिए निलंबित कर दिया गया।

सक्सेना के अभिभाषण के दौरान उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान नारेबाजी व हंगामा करने के कारण यह कदम उठाया गया है।

आप विधायकों की ओर से उत्पन्न व्यवधान को लेकर कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहब सिंह ने सदन में एक प्रस्ताव लाकर अमर्यादित कार्य करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की माँग की, जिसका विधायक अभय वर्मा ने समर्थन करते हुए सभी 21 सदस्यों को तीन दिन के लिए निलंबित करने की माँग की। विधानसभा अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने आप के 21 विधायकों के आज समेत तीन कार्य दिवस के लिए निलंबन का प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया। उल्लेखनीय है कि आप के 22 विधायकों में से ओखला के विधायक अमानतुल्लाह खान आज सदन में मौजूद नहीं थे।

## सरकार सदन...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने और सुरक्षा कर्मियों व पुलिस के खिलाफ विधायक आतिशी का प्रस्ताव लाने की चेतावनी दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह झगड़ा स्पीकर और मुख्यमंत्री का है। अपने आपसी अंतर्कलह की सजा भाजपा जनता को दे रही है।

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा है कि विपक्ष ने गतिरोध दूर करने का हर संभव प्रयास किया है, लेकिन सत्ता पक्ष हठधर्मिता नहीं छोड़ रहा है। हमने पूरे घटनाक्रम पर खेद प्रकट किया। उन्होंने साफ किया कि जब तक गतिरोध खत्म नहीं होता है, हमारा धरना जारी रहेगा। यदि हमारे निलंबित विधायकों सदन में घुसने से रोका गया तो हम विधानसभा के पहिमा द्वार पर धरना देंगे।

गौरतलब है कि 21 फरवरी को सदन में प्रश्नकाल के दौरान मंत्री अविनाश गहलोत की ओर से इंदिरा गांधी को लेकर की गई दादी की टिप्पणी के बाद से सदन में गतिरोध बना हुआ है। सदन में हंगामे के चलते कांग्रेस के छह विधायकों को निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद कांग्रेस के सभी विधायकों ने सदन में धरना दिया था। उसके बाद से लगातार गतिरोध बरकरार है।

राजनैतिक विश्लेषकों को डर है कि हिन्दी भाषी क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने वाली कोई भी पार्टी, दक्षिण भारत के मतदाताओं पर किसी प्रकार की निर्भरता के बिना, केन्द्र में सरकार बना सकती है।

मुख्यमंत्री स्टालिन, इस बिन्दु का नाम लिये बिना, इसी बिन्दु का उठाना चाहते हैं। यह तथ्यशुदा है कि द्रमुक ईकोसिस्टम इस मुद्दे को, तथा इसके साथ ही, भावनात्मक भाषा के मुद्दे को जोर-शोर से उठायेगा, तथा तमिलनाडु में भाजपा के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन के लिये मुश्किल खड़ी हो जायेगी। प्रसंगवश बता दें कि अगर आन्ध्रप्रदेश नई शिक्षा नीति तथा परिसीमन का समर्थन करती है, तो उसे अपनी सफाई देना मुश्किल हो जायेगा। आज सर्वदलीय मीटिंग बुलाने की

संभावना है।

इस समय, इनमें से 4 राज्यों में गैर-भाजपा पार्टियों का शासन है। परिसीमन का आधार एकराज जनसंख्या के आँकड़े होंगे तथा इसलिये परिसीमन के फलस्वरूप सभी दक्षिण भारतीय राज्यों में संसदीय सीटों की संख्या कम हो सकती है।

संसद में अपने राजनैतिक हिस्से पर पड़ने वाले असर को लेकर दक्षिण बहुत चिन्तित बताया जा रहा है क्योंकि उत्तरी भारत के राज्यों की आबादी बहुत

# दिल्ली आबकारी नीति पर सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में पेश हुई

नयी दिल्ली, 25 फरवरी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को विधानसभा में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.) की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जिसमें दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल की विवादास्पद आबकारी नीति के बारे में विभिन्न अनियमितताओं को रेखांकित करते हुये कठोर टिप्पणियाँ की गयी हैं। सी.ए.जी. की रिपोर्ट विधानसभा के सत्र के दूसरे दिन सदन के पटल पर रखी गयी, जिसमें कहा गया है कि दोषपूर्ण 2021-22 आबकारी नीति के कारण दिल्ली सरकार को दो हजार करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय नुकसान हुआ।

‘परफार्मेंस आडिट ऑन रेगुलेशन एंड सप्लाई ऑफ लिक्वर इन दिल्ली’ शीर्षक, इस रिपोर्ट को सदन में विपक्ष की नेता आतिशी सहित आम आदमी पार्टी के 12 विधायकों के निलंबन के बाद पटल पर रखा गया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली में विवादास्पद आबकारी नीति के बारे में सिफारिश के लिये गठित विशेषज्ञ समूह के सुझावों को तत्कालीन उप मुख्यमंत्री एवं आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने नज़रअंदाज कर दिया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि शराब के लाइसेंस वापस किये जाने और शराब जोन की निविदा पुनः जारी करने के

- दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी, जिसमें आबकारी नीति के कारण दो हजार करोड़ रु. के नुकसान की बात की गई है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि इस आबकारी नीति के बारे में सिफारिश के लिए गठित विशेषज्ञ समूह के सुझावों को तत्कालीन उप मुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने नज़रअंदाज कर दिया था।

मामले में आबकारी विभाग की विफलता के कारण विभाग को 890.15 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

सी.ए.जी. की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 की पाबंदियों के नाम पर शराब की दुकान के लाइसेंस धारकों को दी गयी दी 144 करोड़ रुपये की छूट नियमानुसार नहीं थी। छूट के इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग की आपत्तियों

## दो बार होगी दसवीं की परीक्षा

नई दिल्ली, 25 फरवरी। सीबीएसई (सीबीएसई) अब दसवीं कक्षा की परीक्षाएँ दो बार करवाएगा। 2025-26 सत्र में दसवीं की बोर्ड परीक्षा दो बार होगी। ये परीक्षाएँ पूर्ण पाठ्यक्रम पर ही आधारित होंगी।

सीबीएसई ने इसको लेकर 9 मार्च तक लोगों से सुझाव मांगे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बोर्ड परीक्षा में अपना प्रदर्शन सुधारने के लिए छात्रों को दोबारा मौका दिया जा रहा है। हालांकि

- सी.बी.एस.ई. ने इस प्रस्ताव पर 9 मार्च तक लोगों के सुझाव मांगे हैं।

प्रायोगिक परीक्षा या आंतरिक मूल्यांकन केवल एक बार किया जाएगा। दोनों परीक्षाओं के लिए एक ही केन्द्र आवंटित किया जाएगा, वहीं परीक्षा शुल्क में वृद्धि की जाएगी। पहली बोर्ड की परीक्षा 2026 में 17 फरवरी से 6 मार्च तक होगी। वहीं, दूसरी परीक्षा 5 मई से 20 मई के बीच हो सकती है। सीबीएसई ने 2026 से दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएँ साल में दो बार आयोजित करने से जुड़े मसौदा नियमों को मंजूरी दी।

# ‘एक साल में 6 मीटिंग नहीं करने पर कितने नगर परिषद अध्यक्षों को सस्पेंड किया गया है?’

—यादवचेन्ने शर्मा—

जयपुर, 25 फरवरी। राजस्थान हाई कोर्ट में नगर परिषद, दौसा की चयनित अध्यक्ष ममता चौधरी को सस्पेंड करने के खिलाफ दायर रिट याचिका पर सुनवाई हुई। इस मामले में याचिकाकर्ता ममता चौधरी की ओर से पैरवी करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता आर.बी. माथुर और उनके सहायक अधिवक्ता निखिल सिमलोटे और पलक माथुर पेश हुए थे। सुनवाई करते हुए न्यायाधीश महेंद्र कुमार गोयल ने राज्य सरकार को आदेश दिए कि वह शपथ पत्र सहित जवाब पेश करे कि उसने, एक साल में छह बार सभा आयोजित नहीं करने के लिए ममता चौधरी की तरह कितने म्यूनिसिपलिटि या परिषद अध्यक्षों को इस नियम का उल्लंघन करने के लिए सस्पेंड किया है।

दरअसल इस मामले में दौसा स्थित नगर परिषद की अध्यक्ष को 7

- हाई कोर्ट ने दौसा नगर परिषद अध्यक्ष ममता चौधरी के निलम्बन मामले में राज्य सरकार से शपथ पत्र मांगा।
- दौसा में नगर परिषद की अध्यक्ष ममता चौधरी को इसी नियम का उल्लंघन करने के कारण सस्पेंड किया गया था। अदालत जानना चाहती थी कि नगर परिषद की अध्यक्ष के साथ भेदभाव तो नहीं किया जा रहा।

अक्टूबर, 2024 को निलम्बित करने के आदेश दिये गये थे। निलम्बन के आदेश के साथ दी गई रिपोर्ट में कई कारण अंकित थे, जिनमें से एक कारण यह भी था कि अध्यक्ष ने सालभर में कम से कम छह सभाएँ आयोजित करने के नियम का उल्लंघन किया था। राज्य सरकार की ओर से सुनवाई के दौरान इस बिन्दु पर जोर देते हुए बहस की गई थी।

इसके विरोध में वरिष्ठ अधिवक्ता आर.बी. माथुर ने कहा कि उनके मुवकिल के साथ भेद-भाव किया जा

रहा है, क्योंकि पूरे प्रदेश में कई परिषद और म्यूनिसिपैलिटि होंगी, जहां इस नियम का उल्लंघन किया गया हो, परन्तु, सिर्फ उनके ही मुवकिल के साथ भेद-भाव करके निलम्बन के आदेश दिए गए, जबकि किसी भी पार्षद या अधिकारी ने न तो सभा बुलाने के पत्र लिखा या आदेश जारी किए थे। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने स्वायत्त शासन विभाग को शपथ पत्र सहित यह जानकारी देने को कहा है कि पूर्व में इस नियम के उल्लंघन के लिए कितनी परिषदों के अध्यक्षों को हटाया गया है।

इस मामले की अगली सुनवाई 7 मार्च को होगी।

## ‘अगला महाकुंभ...’

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वांगचुक ने कहा, भारत को ग्लेशियर संरक्षण में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि हमारी पवित्र नदियाँ गंगा और यमुना यहीं से निकलती हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के लिए जो कदम उठाए हैं, उनके वे प्रशंसक हैं, खासकर ‘मिशन लाइफ’ अभियान का उन्होंने प्रधानमंत्री से हिमालय के ग्लेशियर्स की स्थिति का आकलन करने के लिए आयोग बनाने की मांग की।

वांगचुक ने कहा, हम सभी जानते हैं कि हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं और अगर बर्फ का पिघलना व जंगलों का विनाश जारी रहा तो कुछ ही दशकों में हमारी पवित्र नदियाँ गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु आदि मौसमी नदियाँ बन जाएँगी, इसका अर्थ होगा कि अगला कुंभ सूखी नदी की रेत पर होगा। उन्होंने कहा, आम लोगों को इस बारे में बहुत कम जानकारी है। वांगचुक ने कहा, हिमालय के ग्लेशियर के आकलन के लिए आयोग बनाया जाए और गंगोत्री व यमुनोत्री जैसे प्रमुख ग्लेशियर्स को राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित किया जाए वांगचुक ने प्रधानमंत्री से मिल कर उन्हें लद्दाख के तेजी से पिघलते ग्लेशियर

का टुकड़ा देने की इच्छा जताई, ताकि उन्हें क्षेत्र के जलवायु प्रभावित लोगों को संदेश दिया जा सके।

उन्होंने कहा कि इस ग्लेशियर वर्ष में मेरी विश्व के सभी नेताओं को ग्लेशियर का टुकड़ा देने की योजना है। मैंने ऐसा ही टुकड़ा यू.एन. को न्यूयॉर्क मुख्यालय में भेंट किया है।

## लैंड फॉर...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

का निर्देश दिया गया है। भ्रष्टाचार के इस मामले में सीबीआई ने 78 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। कोर्ट ने चार्जशीट पर सजा लेते हुए सभी आरोपियों को समन जारी किया है। यह मामला मध्य प्रदेश के जलपुर में स्थित भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य मंडल की की गई समूह ‘डी’ नियुक्तियों से संबंधित है। अधिकारियों के अनुसार, केन्द्रीय रेल मंत्री के रूप में प्रसाद के कार्यकाल के दौरान 2004 और 2009 के बीच राजद सुप्रीमो के परिवार या सहयोगियों को उपहार के रूप में या उनके नाम पर भूखंड हस्तांतरित करने के बदले ये नियुक्तियों की गई।

## परकोटे में बने...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

संबंध में लिए स्वर्णित प्रसंजान पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि रिहायशी क्षेत्र में अवैध निर्माण होना व व्यावसायिक गतिविधियों को संचालित करना कानूनी प्रावधानों की अवहेलना करना है।

सुनवाई के दौरान, एएजी जीएस गिल ने कहा कि अदालती आदेश की पालना में सखे कर भवनों की तीन कैटेगरी बनाई है। पहली कैटेगरी में उन भवनों की इकाई भवनों की संख्या 19 है। वहीं, शेष दो कैटेगरी में बिल्डिंग बायलॉज के खिलाफ जाकर किए गए निर्माणों को शामिल किया गया है। अवैध निर्माण वाली 19 इमारतों पर कार्रवाई की जाएगी। इस पर न्यायमित्र शोभित तिवारी ने कहा कि नगर निगम इन भवनों के खिलाफ पहले ही कार्रवाई कर चुका है और इन्हें सील कर दिया है।

इस पर खंडपीट ने उन्हें कहा कि यदि पहले की कार्रवाई में कोई कमी रही है तो दोबारा इन अवैध भवनों को सील कर दिया जाए। इस मामले में हाईकोर्ट ने प्रमुख यूडीएफ सचिव की कमेटी बनाकर उसे रिपोर्ट देने के लिए कहा था।

रिपोर्ट में 19 भवनों को पूर्णतया और 12 भवनों को आंशिक तौर पर अवैध माना था। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने हल्टियों के साथ-साथ के आबासीय इलाके में व्यावसायिक गतिविधियों पर स्वर्णित प्रसंजान लेते हुए राज्य सरकार व नगर निगम से रिपोर्ट देने के लिए कहा था।

# नीतीश के बेटे निशांत के राजनीति में पदार्पण की अटकलें तेज हुईं

पटना, 25 फरवरी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत के राजनीति में आने को लेकर प्रदेश में चर्चाओं का बाजार गर्म है। निशांत ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत की। ज्ञातव्य है कि राजद नेता तेज प्रताप यादव ने निशांत से राज में शामिल होने की

- निशांत ने आगामी चुनाव में जद (यू) और अपने पिता को विजयी बनाने की अपील की।
- हालांकि, निशांत राजनीति में आने की चर्चाओं पर नीतीश कुमार ने अभी कुछ नहीं कहा है।

अपील की थी। इस पर निशांत ने कहा कि आइए जनता के बीच में चलते हैं, वही बताएगी कि क्या करना है। इस बयान को निशांत के चुनावी राजनीति में आने का संकेत माना जा रहा है। निशांत ने लोगों से आगामी विधानसभा चुनाव में जदयू को और अधिक प्रयत्न पर जिताने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से नीतीश कुमार को लाइला मुख्यमंत्री बताए जाने पर उन्होंने कहा कि गठबंधन में है तो बोलेंगे ही। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने की अपील की। राजनीति में आने को लेकर चल

रही चर्चाओं को लेकर पूछे गए सवाल का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उल्लेखनीय है कि निशांत के राजनीति में आने को लेकर पिछले कई महीनों से चर्चा चल रही है। जदयू कार्यकर्ताओं ने पटना में पार्टी कार्यालय के सामने इसे लेकर पोस्टर भी लगाया था। हालांकि, इस

मामले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और निशांत ने अब तक मुंह नहीं खोला है।

इस कारण यह सवाल अब भी बना हुआ है कि क्या चुनाव के पहले निशांत राजनीति में आएंगे।

## कांग्रेस ला ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कार्यवाही से हटाया जाए। साथ ही मंत्री अपने उस शब्द पर सदन में खेद प्रकट करें और जिन कांग्रेस विधायकों का निलंबन किया है, उस निलंबन को रद्द किया जाए। इसके अलावा उनकी ओर कोई मांग नहीं है।

# केरल में युवक ने प्रेमिका और अपने परिवार के 5 लोगों की हत्या की

तिरुवनंतपुरम, 25 फरवरी। केरल में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। दरअसल तिरुवनंतपुरम में एक युवक ने अपनी प्रेमिका समेत परिवार के पांच लोगों की हत्या कर दी। हमले में युवक की मां गंभीर रूप से घायल हुई है। हत्या की वजह का अभी तक पता नहीं चला है। आरोपी युवक ने भी जहर पीकर आत्महत्या की कोशिश की। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुटी है।

पुलिस ने बताया कि 23 वर्षीय आरोपी युवक अफान ने अपनी दादी, पिता के भाई, पिता के भाई की पत्नी, 14 साल के भाई और अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। आरोपी ने अपनी मां पर भी जानलेवा हमला किया।

# ‘हो सके तो अपने विधायकों को इकट्ठा करके दिखाओ’

चंडीगढ़, 25 फरवरी। पंजाब में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा पर हमला बोलते हुए राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि सत्ताधारी ‘आप’ विधायकों का समर्थन हासिल करने के सपने देखने के बजाय, कांग्रेस को अपनी पार्टी को एकजुट रखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पंजाब विधानसभा में बोलते हुए, मुख्यमंत्री ने विपक्षी नेताओं द्वारा दिए गए बयानों को महज कल्पना और हवाई किला करार दिया, जिसमें कहा गया था कि ‘आप’ के कुछ विधायक कांग्रेस के संर्षक में हैं और पार्टी छोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता न तो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़े हैं और न ही जनता से, इसलिए पंजाब की जनता ने उन्हें नकार दिया है। मान ने कहा कि ये नेता लगातार बेतुके बयान दे रहे हैं, लेकिन इन्होंने कभी

- पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आप के 32 विधायकों के बारे में प्रताप सिंह बाजवा के दावे पर उन्हें चुनौती दी।

केन्द्र सरकार के सामने पंजाब के मुद्दे नहीं उठाए। उन्होंने कहा कि ‘आप’ विधायकों के संर्षक में होने की बात सिर्फ बाजवा की मीडिया में सुर्खियां बटोरने की चाल है। मान ने कांग्रेस नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि ‘आप’ विधायकों की जिंता छोड़कर, उन्हें अपनी पार्टी को एकजुट करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने तर्क करते हुये कहा कि मौजूदा विधानसभा में कांग्रेस के साथ विधायक भी एकजुट होकर काम नहीं कर सकते हैं।